बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 160 ● नई दिल्ली ● वीरवार 09 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

कहने की जरूरत नहीं चुनाव आयोग भाजपा के अंदर काम कर रहा, ईसीआई के पोस्ट पर भड़के केजरीवाल

नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग चुनाव आयोग ने आज अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से बंगाल चुनाव को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसपर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसी मामले में नाराजगी जताते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एक पोस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से चुनाव आयोग के उक्त ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, अब ये कहने की भी जरूरत नहीं कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंदर में काम कर रहा है। ये अब जग जाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिये।

रातभर झमाझम बारिश के बाद दिल्ली की हवा में सुधार, एक्यूआई खिसका, इन इलाकों में जमकर हुई बरसात

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में रात भर हुई बारिश और गरज के साथ हुई बौछारों के कारण बुधवार (8 अप्रैल) को तापमान में काफी गिरावट आई. दिल्ली का एक्यूआई भी खिसक गया है और हवा की क्वालिटी में भी सुधार हुआ है. बुधवार की सुबह न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अप्रैल के शुरुआती दिनों के लिए गर्मी में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाता है. सफदरजंग में स्थित शहर के मुख्य मौसम निगरानी केंद्र ने सुबह 8:30 बजे तक, बीते 24 घंटों में 6.4 मिमी बारिश दर्ज की. चार अप्रैल 2023 को 16.3 मिमी बारिश दर्ज की गई थी जिसके बाद इस साल इतनी बारिश दर्ज की गई है. दिल्ली के कई इलाकों में जमकर बरसात हुई है.

इन इलाकों में हुई जमकर बारिश

अन्य निगरानी केंद्रों में पालम में 4.4 मिमी, लोधी रोड में 5.6 मिमी और रिज में 3.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई. आयानगर में 14.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सभी निगरानी केंद्र में सबसे अधिक है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार को गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से व्यापक बादल छा गए हैं और वर्षा हो रही है.

दिल्ली के तापमान में आई गिरावट

विभिन्न निगरानी केंद्र पर न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस घटकर 16.8 डिग्री सेल्सियस हो गया, पालम में 4.1 डिग्री सेल्सियस घटकर 15.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है. इसके अलावा लोधी रोड में 2.4 डिग्री सेल्सियस घटकर 16.2 डिग्री सेल्सियस हो गया, रिज में 1.9 डिग्री सेल्सियस घटकर 15.3 डिग्री सेल्सियस हो गया और आयानगर में 1.7 डिग्री सेल्सियस घटकर 16.4 डिग्री सेल्सियस हो गया.

दिल्ली की हवा में भी हुआ सुधार

वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया. सुबह नौ बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 82 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को गंभीर माना जाता है.

बहुजन समाज की हिस्सेदारी पर सियासत- राहुल के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, इतिहास का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र के ठेकों में हिस्सेदारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उसे दलित विरोधी करार दिया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में आरोप लगाया कि बड़े सरकारी ठेकों में बहुजन उद्यमियों को सिस्टमेटिक तरीके से बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि पिछले साल दिए गए 16,500 करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्यों के ठेकों में दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय से जुड़े कारोबारों को कितना हिस्सा मिला। राहुल गांधी के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार किया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने कहा कि कांग्रेस की लंबे समय से दलित विरोधी मानसिकता रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, कांग्रेस नेतृत्व ने दलित समुदाय की गरिमा का सम्मान नहीं किया। केसवन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार उन्होंने खुद यह कहा है कि अंतिम निर्णय उनके हाथ में नहीं, बल्कि पार्टी के हाईकमान के पास होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में अध्यक्ष का पद केवल औपचारिक बनकर रह गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान खरगे के साथ किया गया व्यवहार भी पार्टी की कार्यशैली को दिखाता है। केसवन ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने डॉ. बीआर आंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। वहीं, बिहार के मंत्री दीलीप जयसवाल ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से पूछना चाहिए कि पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार क्यों नहीं दिए गए।

वादे, योजनाएं और अब जहां है जैसा है का फैसला, अनधिकृत कॉलोनीवासियों ने नियमित होने को किया लंबा इंतजार

नई दिल्ली । राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा नया नहीं है, बल्कि पिछले कई दशकों से राजनीति, नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच उलझा हुआ बड़ा सवाल है। हर कुछ साल में नई घोषणा, नई योजना और नए वादे सामने आते रहे, लेकिन आज तक यह प्रक्रिया पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाई। अब जहां है जैसा है के फैसले से ऐसी कॉलोनियों में रहने वालों के मन में फिर उम्मीद जगी है। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की शुरुआत 1961 में हुई, जब पहली बार 101 कॉलोनियों को नियमित करने की नीति बनी। इसके बाद 1993 तक 567 कॉलोनियों को नियमित गया लेकिन असली किया विस्तार 1980 के दशक में हुआ। एशियन गेम्स के दौरान जब बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आए और उन्होंने अनधिकृत रूप से बसना शुरू किया। धीरे-धीरे यह कॉलोनियां पूरे शहर में फैल गईं अनुमान है कि दिल्ली की करीब 40 प्रतिशत आबादी इन्हीं में रहती है। 1993 के विधानसभा चुनाव के बाद यह मुद्दा बड़ा राजनीतिक विषय बन गया। क्योंकि यहां रहने वाली बड़ी आबादी वोट बैंक बन चुकी थी। भाजपा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना ने 1071 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। सरकार ने खूब वाहवाही लूटी। हवाई सर्वे कराकर विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा लेकिन यह लागू नहीं हो सका। 2008 में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की कांग्रेस सरकार ने शीला दीक्षित सरकार की पहल पर 1218 कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किए जिससे लोगों को उम्मीद जगी, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकला। अरविंद केजरीवाल ने भी इन कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा की थी। निवासियों के लिए सबसे अहम मोड़ तब आया जब 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएम-उदय योजना शुरू की। इसका उद्देश्य था कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक दिया जाए। तकनीकी जटिलताओं, दस्तावेजों की कमी और प्रक्रियाओं की पेचीदगियों के कारण यह योजना अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी। 2020 से 2023 के बीच 10 लाख मकानों में से सिर्फ 40 हजार को ही कन्वेयंस डीड मिल सकी। अब अप्रैल में केंद्र सरकार ने जहां है जैसा है नीति लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 1731 कॉलोनियों में से 1511 को 45 दिनों के भीतर नियमित करने का लक्ष्य है। हालांकि, चुनौतियां कम नहीं हैं। कई कॉलोनियां रिज एरिया, डीडीए या ग्राम सभा की जमीन पर बसी हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती है।

भारतीय राजनीति के लिए क्षति है...उनका इस तरह से जाना हमें दुखी करता है- मोहसिना किदवई के निधन पर बोलीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत

नोएडा । गांधी परिवार की करीबी एंव कांग्रेस सरकार में मंत्री रही मोहसिना किदवई के निधन पर कांग्रेस कार्यकताओं में शोक की लहर दोड़ पड़ी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत उनके नोएडा स्थित अवास में मिलने के लिए पहुंची इस दौरान उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि-मोहसिना किदवई जी से मेरा संबंध पिताजी के समय से है उनका मेरे पिता से बहुत स्नेह था और फिर मुझसे उनका स्नेह हुआ। मोहसिना किदवई उत्तर प्रदेश जैसे पुरुष प्रधान राय में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और वहां पर उन्होंने राजनीति की वही उनकी पहचान थी, संगठन के माध्यम से जितने लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया उसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति के लिए क्षति है। उनका इस तरह से जाना हमें दुखी करता है लेकिन इस बात का गर्व है कि मोहसिना किदवई जैसी नेता हमारी बीच थी दशकों पहले उन्होंने अपनी पहचान राजनीति में बनाई।

मोहसिना किदवई का 93 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन

आप को बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का 93 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। राजनीतिक जीवन में लंबे समय तक सक्रिय रहीं मोहसिना किदवई ने केंद्र और राय सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके निधन पर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं समेत परिवार और प्रशंसकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। नोएडा के सेक्टर 40 स्थित आवास से मोहसिना किदवई की अंतिम यात्रा दोपहर 3 बजे निकलेगी। दिल्ली के निजामुद्दीन कब्रिस्तान में शाम पांच बजे उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान किदवई ने स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन और नागरिक उड्डयन जैसे मंत्रालयों में काम किया। 1 जनवरी, 1932 को बाराबंकी में जन्मीं मोहसिना किदवई दो बार छत्तीसगढ़ से रायसभा सदस्य भी चुनी गईं। वह 1978 उपचुनाव, 1980 और 1984 में मेरठ से सांसद चुनी गईं। इसके बाद 2004 से 2010 और 2010 से 2016 तक रायसभा की सदस्य रहीं। गांधी परिवार की करीबी रहीं मोहसिना किदवई केंद्र सरकार में मंत्री के अलावा हज कमेटी की अध्यक्ष भी रहीं। उन्होंने कांग्रेस महासचिव के रूप में भी काम किया। वह कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य भी रहीं। वह लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मोहसिना किदवई के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मोहसिना किदवई बेहद सौम्य स्वभाव की थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- धर्म में अंधविश्वास क्या है, इसका फैसला करने का हमें अधिकार; सरकार का विरोध

नई दिल्ली ।सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े 2018 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट अब धर्म के भीतर अंधविश्वास की परिभाषा तय करने के अधिकार क्षेत्र पर विचार कर रहा है। बुधवार को एक नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण अवलोकन किया कि किसी धर्म में कौन सी प्रथा अंधविश्वास है, यह तय करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र रखता है। यह टिप्पणी केंद्र सरकार की उस दलील के जवाब में आई, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एक धर्मनिरपेक्ष अदालत इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं, न कि धर्म के। मेहता ने तर्क दिया कि यदि कोई प्रथा अंधविश्वास मानी भी जाती है, तो यह तय करना अदालत का काम नहीं है, बल्कि संविधान के अनुछेद 25(2)(बी) के तहत विधायिका का काम है कि वह सुधार कानून बनाए। उन्होंने कहा कि विधायिका किसी विशेष प्रथा को अंधविश्वास बताकर उसमें सुधार कर सकती है, जैसा कि जादू-टोना और अन्य ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। हालांकि, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने मेहता के इस तर्क को बहुत सरल बताते हुए कहा कि अदालत के पास यह तय करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र है कि कोई चीज अंधविश्वास है या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बाद क्या होगा, यह विधायिका का काम है, लेकिन अदालत में यह नहीं कहा जा सकता कि विधायिका का निर्णय ही अंतिम होगा। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने यह भी तर्क दिया कि एक धर्मनिरपेक्ष अदालत यह तय नहीं कर सकती कि कोई धार्मिक प्रथा केवल अंधविश्वास है, क्योंकि अदालत के पास ऐसी विद्वत्तापूर्ण क्षमता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा आप (न्यायाधीश) कानून के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, धर्म के नहीं। मेहता ने यह भी कहा कि नागालैंड के लिए जो धार्मिक हो सकता है, वह किसी और के लिए अंधविश्वास हो सकता है, क्योंकि समाज अत्यंत विविध है। इस पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि यदि जादू-टोना को धार्मिक प्रथा का हिस्सा माना जाए, तो क्या उसे अंधविश्वास नहीं माना जाएगा? उन्होंने मेहता से पूछा कि यदि अदालत के पास अनुछेद 32 के तहत ऐसी याचिका आती है कि जादू-टोना की एक धार्मिक प्रथा मौजूद है, और विधायिका खामोश है, तो क्या अदालत खाली क्षेत्र के सिद्धांत का उपयोग करके स्वास्थ्य, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रथा को प्रतिबंधित करने का निर्देश नहीं दे सकती? सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है क्योंकि यह स्वास्थ्य, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, न कि इसलिए कि यह अंधविश्वास है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसी आवश्यक धार्मिक प्रथा को निर्धारित करते समय, अदालत को उस विशेष धर्म की फिलॉसफी के लेंस से देखना चाहिए। उन्होंने कहा, आप किसी अन्य धर्म के विचारों को लागू नहीं कर सकते और कह सकते हैं कि यह आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। अदालत का दृष्टिकोण उस धर्म की फिलॉसफी को लागू करना है, जो स्वास्थ्य, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन हो।

पर्दे के पीछे अपने मतलब का खेल

पाकिस्तान की विदेश नीति को अगर सीधे शब्दों में समझना हो तो यह साफ दिखता है कि वह एक साथ दो खेल खेलता है। सामने दोस्ती, पीछे साजिश यही उसकी पहचान बन चुकी है। हाल के घटनाक्रम ने इसे और उजागर कर दिया है। पिछले साल जून में जब पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी तो इसके पीछे गहरी रणनीति छिपी थी। इस एक बैठक ने दिखा दिया था कि पाकिस्तान कैसे एक तरफ खुद को सहयोगी बताता है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अपने मतलब का खेल खेलता रहता है। बताया जाता है कि इस मुलाकात में ईरान के मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई थी। यह भी चर्चा में रहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के ठिकानों के इस्तेमाल की संभावना टटोली। इससे भी गंभीर आरोप यह है कि पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु ठिकानों से जुड़ी जानकारी अमेरिका को उपलब्ध कराई, जिसके आधार पर पिछले साल ही ईरान में अमेरिकी हमला हुआ था। यह न केवल विश्वासघात है बल्कि मुस्लिम दुनिया में भी एक गहरी दरार का संकेत देता है। देखा जाये तो पाकिस्तान और ईरान के संबंध कभी भी सहज नहीं रहे। एक ओर धार्मिक मतभेद है जहां सुन्नी और शिया का सवाल हमेशा तनाव का कारण बना रहा, वहीं दूसरी ओर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है। पाकिस्तान खुद को इस्लामी दुनिया की एकमात्र परमाणु शक्ति के रूप में देखता रहा है और वह नहीं चाहता कि कोई और मुस्लिम देश इस श्रेणी में आए। ऐसे में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान के लिए असहजता का कारण बनता है। यही वजह है कि पाकिस्तान खुले मंच पर भले ही तटस्थता की बात करे, लेकिन पर्दे के पीछे वह अलग खेल खेलता दिखता है। यह दोहरापन सिर्फ ईरान के मामले तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान एक ओर अमेरिका के साथ खुफिया सूचनाएं साझा करता है, वहीं दूसरी ओर खुद को शांति दूत के रूप में प्रस्तुत करता है। ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध में पाकिस्तान ने शांति वार्ता कराने की पहल का दिखावा किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में शांति की कोशिश थी या अपनी छवि सुधारने का प्रयास था? इस पूरे खेल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक तरफ वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति और सहयोग की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार की नीतियां और फैसले पाकिस्तान की दोहरी रणनीति को मजबूत करते हैं। यह एक तरह का सुनियोजित भ्रम है जिसमें दुनिया को एक चेहरा दिखाया जाता है और दूसरा चेहरा छिपा रहता है। साथ ही अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध भी इस संदर्भ में दिलचस्प हैं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपने पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर चुके हों, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उनका रुख बदला हुआ नजर आता है। इसकी एक वजह यह भी है कि ट्रंप परिवार का पाकिस्तान में आर्थिक निवेश है। ऐसे में रणनीतिक हित और निजी हित एक दूसरे में घुलते नजर आते हैं। यही सबसे खतरनाक पहलू है कि अमेरिका पाकिस्तान के इस खुले दोहरे चरित्र को भलीभांति समझता है, फिर भी जानबूझकर उसे नजरअंदाज करता है। यह कोई मजबूरी नहीं बल्कि सोची समझी चाल है। हालिया संघर्षविराम का श्रेय पाकिस्तान को देना इसी खेल का हिस्सा है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान एक तरफ आग को हवा देता है और दूसरी तरफ खुद को बुझाने वाला बताता है, फिर भी वह इस्लामाबाद को आगे करता है ताकि अपने रणनीतिक हित साध सके। दूसरी ओर पाकिस्तान इस मौके को ऐसे भुनाता है मानो वह दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत हो, जबकि हकीकत यह है कि वही पर्दे के पीछे हालात बिगाड़ने में भी शामिल रहता है। यह पूरी कहानी एक सुनियोजित नाटक की तरह है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान दोनों अपने अपने किरदार निभा रहे हैं और दुनिया को गुमराह किया जा रहा है। यहां असल सवाल यह है कि क्या दुनिया इस दोहरे खेल को समझ रही है? पाकिस्तान लंबे समय से इसी रणनीति पर काम करता आया है। अफगानिस्तान के मामले में भी उसने एक तरफ अमेरिका का साथ दिया और दूसरी तरफ तालिबान को समर्थन दिया। अब वही नीति ईरान के संदर्भ में दिखाई दे रही है। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी इस रणनीति को नए स्तर पर ले जाती दिख रही है। सेना और सरकार के बीच तालमेल के जरिए एक ऐसा तंत्र तैयार किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भ्रम पैदा करने में सक्षम है। यह सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक सुनियोजित छवि प्रबंधन है। दुनिया के लिए यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की नीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पीछे गहरी रणनीतिक सोच काम करती है। जब तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस दोहरे चरित्र को पहचान कर उसके अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देगा, तब तक पाकिस्तान इसी तरह दो नावों पर सवार होकर अपने हित साधता रहेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान आज भी विश्वास और संदेह के बीच खड़ा देश है। उसके कदमों में स्थिरता नहीं बल्कि अवसरवादिता झलकती है। बहरहाल, ईरान के खिलाफ युद्ध में संघर्षविराम के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत साबित करने में जुटे हैं। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत रखने वाले ट्रंप का अपने दूसरे कार्यकाल में युद्ध भड़काना और फिर सभ्यता खत्म कर देने जैसी धमकियां देना उनके असली चरित्र को उजागर करता है। इसी कड़ी में पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, जो इस संघर्ष में मध्यस्थता का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात करता है, जबकि दूसरी ओर उसी पर दुनिया भर में अशांति और आतंकवाद फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। सच यह है कि यह पूरा घटनाक्रम शांति का नहीं बल्कि दोहरे चरित्र और अवसरवादी राजनीति का एक और उदाहरण बनकर सामने आया है, जिसे अब दुनिया साफ साफ समझने लगी है।

भारतीय समाज :- रिश्तों में आती दरारें

भारतीय समाज सदियों से अपने मजबूत पारिवारिक मूल्यों, आपसी प्रेम, विश्वास और सामूहिकता के लिए जाना जाता रहा है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली रही है। यहां रिश्तों की डोर केवल खून के संबंधों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पड़ोसी, मित्र और समाज के हर व्यक्ति के साथ आत्मीय जुड़ाव महसूस किया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में यह सुगंध धीरे-धीरे फीकी पड़ती महसूस होती है। रिश्तों में दरारें बढ़ रही हैं और विश्वास का आधार कमजोर होता जा रहा है। आज के दौर में सबसे बड़ा बदलाव जीवनशैली में आया है। भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रतिस्पर्धा और भौतिक सुख-सुविधाओं की अंधी दौड़ ने इंसान को आत्मकेंद्रित बना दिया है। पहले परिवार के साथ बैठकर भोजन करना, सुख-दुख साझा करना और एक-दूसरे की भावनाओं को समझना सामान्य बात थी। लेकिन अब मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने वास्तविक संवाद को काफी हद तक कम कर दिया है। लोग आभासी दुनिया में अधिक सक्रिय हैं, जबकि वास्तविक रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है। रिश्तों में दरार का एक प्रमुख कारण संवाद की कमी है। जब लोग खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते, तो गलतफहमियां जन्म लेती हैं। छोटी-छोटी बातों को दिल में रखना, अहंकार के कारण पहल न करना और अपनी गलती स्वीकार न करना, ये सभी बातें रिश्तों को कमजोर करती हैं। पहले परिवार में बुजुर्गों का मार्गदर्शन होता था, जो हर विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभाते थे। आज संयुक्त परिवारों का विघटन होने से यह संतुलन भी टूट गया है। आर्थिक दबाव भी रिश्तों पर गहरा असर डाल रहा है। बढ़ती महंगाई, नौकरी की अनिश्चितता और करियर की चिंता ने लोगों को मानसिक रूप से तनावग्रस्त कर दिया है। इस तनाव का प्रभाव सीधे पारिवारिक संबंधों पर पड़ता है। पति-पत्नी के बीच विवाद, माता-पिता और बच्चों के बीच दूरी और भाई-बहनों के बीच संपत्ति को लेकर झगड़े, ये सब आज के समाज में आम होते जा रहे हैं। रिश्ते अब भावनाओं की बजाय स्वार्थ और लाभ-हानि के तराजू पर तोले जाने लगे हैं। इसके अलावा, बदलती सोच और पीढ़ियों के बीच बढ़ता अंतर भी रिश्तों में खटास का कारण बन रहा है। नई पीढ़ी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्पेस को प्राथमिकता देती है, जबकि पुरानी पीढ़ी पारंपरिक मूल्यों को महत्व देती है। इस सोच के टकराव से टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि दोनों पीढ़ियां एक-दूसरे को समझने का प्रयास करें, तो इस दूरी को कम किया जा सकता है लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। मीडिया और मनोरंजन के बदलते स्वरूप ने भी समाज के मूल्यों को प्रभावित किया है। फिल्मों और धारावाहिकों में दिखाए जाने वाले संबंधों की जटिलता और कभी-कभी नकारात्मक चित्रण का प्रभाव लोगों की सोच पर पड़ता है। इससे रिश्तों के प्रति लोगों की धारणा बदलती है और वे वास्तविक जीवन में भी उसी तरह के व्यवहार को अपनाने लगते हैं। हालांकि स्थिति पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। आज भी भारतीय समाज में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहां लोग रिश्तों को संजोकर रखते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। जरूरत है तो केवल इस बात की कि हम अपने मूल्यों को पुन: पहचानें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। रिश्तों की सुगंध को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है संवाद और समझ। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिए। छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना और माफी मांगने की आदत विकसित करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही, हमें भौतिक सुख-सुविधाओं की दौड़ में मानवीय मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। पैसा और सफलता जरूरी है लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण हैं हमारे रिश्ते और उनका स्नेह। परिवार के साथ बिताया गया समय, एक-दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना, यही असली सुख का आधार है। शिक्षा प्रणाली में भी नैतिक मूल्यों और जीवन कौशल पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है, ताकि नई पीढ़ी रिश्तों के महत्व को समझ सके। माता-पिता और शिक्षक बच्चों को केवल करियर की दिशा ही न दिखाएं, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की भी प्रेरणा दें। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय समाज में रिश्तों की सुगंध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि वह कहीं न कहीं दब गई है। जरूरत है उसे फिर से जागृत करने की। यदि हम अपने व्यवहार में थोड़ी संवेदनशीलता, समझदारी और प्रेम जोड़ लें, तो यह सुगंध फिर से पूरे समाज को महका सकती है। रिश्ते जीवन की सबसे अनमोल पूंजी हैं। इन्हें संजोकर रखना ही हमारे समाज की असली पहचान है। यदि हम आज भी नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा समाज मिलेगा, जहां संबंध केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। इसलिए समय की मांग है कि हम रिश्तों की इस टूटती डोर को फिर से मजबूती से बांधें और भारतीय समाज की उस पुरानी सुगंध को पुन जीवंत करें।

सम्पादकीय...

आत्मा को झिंझोड़ गया

हमारी यह दुनिया नफरतों के आखरी स्टेज में है,अब इसका इलाज, मुहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं! प्रख्यात शायर, चरण सिंह बशर के इस शेर पर लोगों ने सिर धुन लिया और खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि यह शेर और बहुत से और शेर व ग़ज़लें, इस समय विश्व में चल रहे युद्ध और बर्बादी पर थे। इस अवसर पर साहिर लुधियानवी की युद्ध के विरुद्ध बुद्ध की बात करती कविता भी प्रसिद्ध उर्दू कवि इकबाल अशहर ने शुरू में विश्व विख्यात और 1944 से चल रहे शंकर-शाद मुशायरे में पढ़ी जो आज के जंग के परिदृश्य में पूर्ण रूप से फिट थी। देश का सबसे पुराना मुशायरा, अर्थात शंकर-शाद मुशायरा एक सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, जिसमें उर्दू शायरी की खूबसूरती, ग़ज़ल, नज़्म और अदबी माहौल का संगम देखने को मिलता है। शंकर-शाद : आमतौर पर यह नाम दो शख्सियतों या परंपराओं के मेल को दर्शाता है-शंकर (हिंदू सांस्कृतिक प्रतीक) और शाद (उर्दू/मुस्लिम अदबी रंग)। इस मुशायरे की एक विशेषता यह भी है कि इसने शायरी से इश्क रखने वाले सभी हिन्दुस्तानियों और पाकिस्तानियों के दिल जोड़े। दरअसल इस मुशायरे की शुरुआत पाकिस्तान के लायलपुर (अब फैसलाबाद) में डीसीएम श्रीराम दौलत के मालिक लाला श्रीराम ने पहला मुशायरा इंडो-पाक मुशायरा के नाम से कराया था, जो हिंद-पाक युद्धों के कारण बंद रहा मगर आज भी दिल्ली के मॉडर्न स्कूल के अंदर उसकी 57वीं नशिस्त लगी, जिसमें हर उम्र और विशेष रूप से इतने अधिक युवा वर्ग के लोग थे कि हॉल में स्थान न मिलने के कारण उर्दू शायरी के उतने ही चाहने वाले बाहर बास्केटबॉल कोर्ट्स पर बैठे बड़े स्क्रीनों पर देख रहे थे। इस मुशायरे में प्रो. वसीम बरेलवी, जावेद अख्तर, शीन काफ निज़ाम, राजेश रेड्डी, इकबाल अशहर, चरण सिंह बशर, शबीना अदीब, शकील आज़मी, अज़हर इकबाल, हिलाल फरीद, मुकेश कुमार तैश, हिना हैदर रिज़वी, सैफ़ निज़ामी और जुबैर अली ताबिश ने ऐसा समा बांधा कि लोग लगातार मुकर्रर, जबरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब, बेमिसाल आदि की गुहारें लगाते रहे। ये मुशायरे और कवि सम्मेलन हमारी साझा विरासत और गंगा-जमुनी परंपरा का पता देते हैं। शेर-ओ-शायरी वास्तव में जीवन के सभी भावों को बड़ी सूक्ष्मता से छूती है। ख्यातिप्राप्त अज़ीम शायर, प्रो. वसीम बरेलवी का शेर मन, मस्तिष्क और आत्मा को छू गया। उसूलों पर जब आंच आए, तो टकराना जरूरी है,जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है! ऐसे ही एक और विश्व विख्यात शायर और मुंबई फिल्म जगत के बड़े नाम, राजेश रेड्डी ने क्या खूब कहा-मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिन्दगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।लाला श्रीराम की खासियत थी कि वे बड़े ही संस्कारी और मेहमाननवाज थे। कर्ज़न रोड (कस्तूरबा गांधी मार्ग) पर अपनी कोठी पर वे आए दिन शायरी की बैठकें रखते, जिसके बाद चाय, भोजन आदि की दावतें होतीं। संस्कारी इतने थे कि जब तक दस्तरखान पर खाने नहीं आते जब तक एक-एक व्यक्ति अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता। ये संस्कार अभी इस परिवार से लुप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि आज भी इनकी पासदारी और रखवाली, इस पीढ़ी के मौजूदा सर्वेसर्वा, माधव बंसीधर श्रीराम कर रहे हैं, जिन्हें उर्दू से उतना ही प्यार है जितना इनके पुरखों को।

20 करोड़ भूखे पेट, 8 करोड़ टन भोजन बर्बाद, नुकसान पर नकेल जरूरी

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, फसल कटने के बाद की कमजोर व्यवस्था, जैसे ढके हुए गोदामों की कमी, कोल्ड-चेन में निवेश की कमी, मशीनों की समय पर उपलब्धता न होना, ग्रेड्सझडग और वैज्ञानिक पैकेजिंग की कमी, ये सब बड़ी बाधाएं पंजाब में है।

कीमत धरती चुका रही - भोजन की बर्बादी सिर्फ इंसानी त्रासदी नहीं, यह पर्यावरणीय संकट भी है। दुनिया में कुल ग्रीनहाउस गैस में से 8 से 10 प्रतिशत भोजन की बर्बादी से पैदा हो रही है। जब खाना कचरे में सड़ता है तो इससे निकलने वाली मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना यादा खतरनाक है। हर दाना बर्बाद होने का मतलब है पानी, जमीन, ईंधन, खाद, बीज, कीटनाशक और किसान की मेहनत का नुकसान। एक किलो चावल उगाने में करीब 5000 लीटर पानी लगता है। जब वह चावल फेंका जाता है, तो वह पानी भी बर्बाद होता है, खासकर पंजाब जैसे राय में, जहां भूजल तेजी से गिर रहा है। समय की मांग है कि खाद्यान्न की बर्बादी को जलवायु नीति में शामिल किया जाए।

हर साल 30 मार्च को पूरी दुनिया 'इंटरनैशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट' मनाती है। 2026 में इसका फोकस भोजन की बर्बादी पर ध्यान आकर्षित करता है। यह सिर्फ एक थीम नहीं, बल्कि एक नैतिक संकट है, जो हमें सबसे दर्दनाक सच्चाई से रूबरू कराता है। जो खाना बर्बाद होता है, उसे किसी किसान ने कड़ी मेहनत से तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए उगाया था। खेत से मंडियों तक उन मजदूरों ने पहुंचाया जिन्हें खुद पेट भर खाने को नहीं मिल रहा। यूनाइटेड नेशंस एन्वायरनमेंट प्रोग्राम (यू.एन.ई.पी.) की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 बताती है कि दुनिया में 105 करोड़ टन खाना बर्बाद हुआ। इसमें से 60 प्रतिशत बर्बादी घरों और खाद्य भंडारण व्यवस्था के कारण हुई, 28 प्रतिशत होटल-रेस्टोरेंट सैक्टर में और 12 प्रतिशत रिटेल में। यह सिर्फ लोगों की लापरवाही की समस्या नहीं, यह पूरी व्यवस्था की खामी है, सप्लाई चेन की कमजोरियां, नीतियों की कमी और एक ऐसी सोच, जिसमें खाना फेंक देना सामान्य बात बन गई है। दूसरी तरफ दुनिया में करीब 78.3 करोड़ लोग आज भी भूख झेल रहे हैं और 30 लाख से यादा लोग संतुलित आहार से वंचित हैं। ऐसे में फसल कटने के बाद होने वाले नुकसान और खाने की बर्बादी को रोकना बेहद जरूरी है। एक तरफ करोड़ों टन अन्न बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी ओर करोड़ों लोग भूखे पेट सो रहे हैं, कुपोषण अब भी दुनिया में फैला है। यह विडंबना नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की असफलता है। भारत कहां खड़ा है - इस पूरे संकट में भारत की स्थिति गंभीर और असहज करने वाली है। यू.एन.ई.पी. की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया में खाद्यान्न बर्बादी में दूसरे नंबर पर है। हर साल 7.8 से 8 करोड़ टन भोजन व फसल बर्बाद होती है, जिसकी कीमत करीब 1.55 लाख करोड़ रुपए बैठती है। चीन पहले नंबर पर है, जहां 10.80 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। अमेरिका में 2.4 करोड़ टन, जर्मनी में 65 लाख टन और जापान में, जहां 'मोत्तैनाई' यानी चीजों को व्यर्थ न जाने देने की संस्कृति है, केवल 52 लाख टन खाना बर्बाद होता है। भारत में हर व्यक्ति साल में औसतन 55 किलो खाना बर्बाद करता है, जो अमेरिका (73 किलो) और जर्मनी (75 किलो) से कम है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ग्लोबल हंगर इंडैक्स में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है, करीब 19.4 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इसलिए भोजन की बर्बादी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह करोड़ों लोगों के मुंह से छिना हुआ निवाला है। पंजाब अन्नदाता लेकिन रिसता हुआ भंडार - पंजाब, जो करोड़ों लोगों का पेट भर सकता है लेकिन खेत की उपज का एक बड़ा हिस्सा प्लेट तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। पंजाब में फल और सब्जियों की लगभग 20 प्रतिशत फसल खाने तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है। वर्ष 2019 से 2024 के बीच अकेले एफ.सी.आई. के गोदामों में ही 8200 टन अनाज खराब हुआ, जो देश में सबसे यादा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, फसल कटने के बाद की कमजोर व्यवस्था, जैसे ढके हुए गोदामों की कमी, कोल्ड-चेन में निवेश की कमी, मशीनों की समय पर उपलब्धता न होना, ग्रेड्सझडग और वैज्ञानिक पैकेजिंग की कमी, ये सब बड़ी बाधाएं पंजाब में हैं।कीमत धरती चुका रही - भोजन की बर्बादी सिर्फ इंसानी त्रासदी नहीं, यह पर्यावरणीय संकट भी है। दुनिया में कुल ग्रीनहाउस गैस में से 8 से 10 प्रतिशत भोजन की बर्बादी से पैदा हो रही है। जब खाना कचरे में सड़ता है तो इससे निकलने वाली मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना यादा खतरनाक है। हर दाना बर्बाद होने का मतलब है पानी, जमीन, ईंधन, खाद, बीज, कीटनाशक और किसान की मेहनत का नुकसान। एक किलो चावल उगाने में करीब 5000 लीटर पानी लगता है। जब वह चावल फेंका जाता है, तो वह पानी भी बर्बाद होता है, खासकर पंजाब जैसे राय में, जहां भूजल तेजी से गिर रहा है। समय की मांग है कि खाद्यान्न की बर्बादी को जलवायु नीति में शामिल किया जाए। आगे की राह - खाद्यान्न नुकसान को कम करना सिर्फ फसल या बचे हुए खाने को संभालना नहीं, यह सोच बदलने की जरूरत है कि हम खाने को कैसे देखते हैं, कैसे सहेजते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। बर्बादी कम करने के लिए हमें पूरी व्यवस्था, प्रोत्साहन और सोच बदलनी होगी और इसमें किसान की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए पांच व्यावहारिक कदम जरूरी हैं।

1. कोल्ड-चेन बनाओ, नुकसान की चेन तोड़ो - भारत अपनी कुल उपज का सिर्फ 8 प्रतिशत प्रोसैस करता है, जबकि अमेरिका 65 प्रतिशत व चीन 23 प्रतिशत। कोल्ड-चेन व प्रोसैसिंग को फूड सिक्योरिटी का हिस्सा माना जाए।
2. बर्बादी रोकने के लिए बने कानून - यूरोप के कई देशों में सुपरमार्कीटों के लिए खाना फैंकना गैरकानूनी है, उन्हें फूड बैंक को दान करना होता है। भारत में भी ऐसा कानून होना चाहिए और दान करने वालों को टैक्स में छूट दी जा सकती है।
3. किसान को मजबूत बनाओ - भोजन का नुकसान खेत से ही शुरू होता है। किसान उत्पादक संगठनों को मशीनें, आधुनिक स्टोरेज और मोबाइल कोल्ड यूनिट्स दी जानी चाहिए। जूट बैग में अनाज रखने की पुरानी व्यवस्था को बदलकर आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए।
4. बर्बादी बताओ - भारत में अभी भोजन बर्बादी का कोई मानिटरिंग सिस्टम नहीं है। बड़े होटल, शादी-ब्याह कैटरिंग और संस्थानों में बर्बादी का रिकॉर्ड रखना और इसे सार्वजनिक करना जरूरी किया जाए।
5. 'अन्न' का सम्मान करें - हमारी संस्कृति में अन्न को भगवान माना गया है-'अन्न ही ब्रह्म है।' यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि सबसे टिकाऊ सोच है। स्कूलों, समाज और संस्थानों में इस भावना को जिम्मेदारी के रूप में जीवित करना होगा। समय की मांग है कि भोजन की बर्बादी रोकना राष्ट्रीय प्राथमिकता बने।

ज़ब अधिकार अत्याचार का माध्यम बन गए थे- न्याय की जीत सत्यमेव जयते

वैश्विक स्तरपर साल 2020 में जब पूरी दुनियाँ कोविड -19 महामारी के अभूतपूर्व संकट से जूझ रही थी, तब सरकारों ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त लॉकडाउन जैसे कदम उठाए।भारत भी इससे अछूता नहीं रहा।सड़कों पर सन्नाटा,बंद बाजार,ठप उद्योग यह दृश्य देशभर में आम था। लेकिन इस सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के बीच एक दूसरा,कम दिखाई देने वाला संकट भी पनप रहा था,सत्ता के दुरुपयोग और मानवाधिकारों के उल्लंघन का। कई स्थानों पर पुलिस और प्रशासन को व्यापक अधिकार दिए गए, जिनका उद्देश्य कानून- व्यवस्था बनाए रखना था,परंतु कुछ मामलों में यही अधिकार अत्याचार का माध्यम बन गए। इसी पृष्ठभूमि में तमिलनाडु के सातानकुलम में घटित कस्टोडियल डेथ का मामला सामने आया, जिसने न केवल भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तरपर भी न्याय और मानवाधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इस कस्टोडियल डेथ मैटर में न्यायपालिका की भूमिका- लोकतंत्र का अंतिम स्तंभ सिद्ध हुई, इस केस में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए न केवल सख्त सजा दी, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वे आम नागरिक हों या पुलिसकर्मी। यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसे फैसले लोकतंत्र में विश्वास को मजबूत करते हैं और यह संदेश देते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। प्रिंट इलेक्ट्रानिक और डिजिटल मीडिया में अक्सर हम कस्टोडियल डेथ के बारे में बहुत सुनते हैं,इसलिए अब पुलिस सुधार की आवश्यकता- प्रणालीगत बदलाव की मांग का समय अब आ गया है। सातानकुलम केस ने भारतीय पुलिस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है, जैसे कि हिरासत में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता, स्वतंत्र जांच एजेंसियों की स्थापना, और पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण में मानवाधिकारों पर जोर।इसके अलावा, पुलिस बल में कार्य के दबाव, संसाधनों की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दों को भी संबोधित करना आवश्यक है। जब तक इन संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति की संभावना सटीक रूप से बनी रहेगी। साथियों बात अगर हम सातानकुलम की घटना- एक सामान्य उल्लंघन से असाधारण त्रासदी तक इसको समझने की करें तो19 जून 2020 को तमिलनाडु के सातानकुलम में एक सामान्य-सी दिखने वाली घटना ने भयावह रूप ले लिया। मोबाइल दुकान चलाने वाले पी. जयराज (59) और उनके बेटे जे. बेनिक्स (31) पर आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी दुकान खुली रखी। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और थाने ले जाया गया। सामान्यतः ऐसे मामलों में जुर्माना या चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है,लेकिन इस केस में पुलिस की कार्रवाई असामान्य रूप से कठोर और अमानवीय साबित हुई।परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों को पूरी रात थाने में बर्बरता पूर्वक पीटा गया। उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे,खून बह रहा था और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया।यह केवल कानून का पालन कराने की कार्रवाई नहीं थी,बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का चरम उदाहरण बन गई।बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया,लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि कुछ ही दिनों में 22 जून को बेनिक्स और 23 जून को जयराज की मृत्यु हो गई। साथियों बात अगर हम पुलिस का प्रारंभिक बचाव और सच्चाई का उजागर होना इसको समझने की करें तो इस घटना के बाद पुलिस ने प्रारंभ में यह दावा किया कि दोनों की मौत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुई है। यह एक सामान्य रणनीति थी, जिसे अक्सर कस्टोडियल डेथ के मामलों में अपनाया जाता है।लेकिन इस बार परिस्थितियाँ अलग थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के दावों की पोल खोल दी। रिपोर्ट के अनुसार, बेनिक्स के शरीर पर 13 और जयराज के शरीर पर 17 गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जो स्पष्ट रूप से अत्यधिक हिंसा और प्रताड़ना की पुष्टि करते थे।इसके अलावा, एक महिला कॉन्स्टेबल के बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया। उसने खुलासा किया कि दोनों को रातभर बेरहमी से पीटा गया और उनके खून से सने कपड़ों से थाने की सफाई करवाई गई। यह केवल शारीरिक हिंसा नहीं थी, बल्कि मानवीय गरिमा का घोर अपमान था। इस खुलासे के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया और यह मामला राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गया।

साथियों बात अगर हम न्याय की लंबी यात्रा छह वर्षों का संघर्ष इसको समझने की करें तो यह मामला केवल एक आपराधिक केस नहीं था, बल्कि न्याय के लिए लंबी और कठिन लड़ाई का प्रतीक बन गया। छह वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान कई बाधाएँ आईं सबूतों का संरक्षण, गवाहों की सुरक्षा, और न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताएँ। कुल 10 आरोपियों में से एक की कोविड के दौरान मृत्यु हो गई,जबकि बाकी 9 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहा।6 अप्रैल 2026 को मदुरै की फर्स्ट एडिशनल सेशंस कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा, जो भारतीय न्याय प्रणाली में सबसे गंभीर अपराधों के लिए आरक्षित है। जज मुथुकुमारन ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला केवल हत्या का नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और मानवीय गरिमा के उल्लंघन का है, और ऐसी स्थिति में उम्रकैद भी पर्याप्त नहीं है। साथियों बात अगर हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर का सिद्धांत और इस केस में उसका अनुप्रयोग को समझने की करें तो,भारतीय न्याय प्रणाली में रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत का उपयोग बहुत ही सीमित मामलों में किया जाता है। यह सिद्धांत बचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के ऐतिहासिक फैसले से विकसित हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मृत्युदंड केवल उन्हीं मामलों में दिया जाना चाहिए, जहाँ अपराध अत्यंत क्रूर, अमानवीय और समाज के लिए असाधारण खतरा हो।सातानकुलम केस में अदालत ने पाया कि पुलिसकर्मियों ने न केवल कानून का उल्लंघन किया, बल्कि वे स्वयं कानून के संरक्षक होने के बावजूद अपराधी बन गए। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए निहत्थे और निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार किया। इस प्रकार, यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में पूरी तरह फिट बैठता है। साथियों बात अगर हम इस केस में सजा और मुआवजा न्याय का बहुआयामी दृष्टिकोण को समझने की करें तोअदालत ने केवल मृत्युदंड ही नहीं दिया, बल्कि दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ 40 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह निर्णय न्याय के बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें अपराधियों को सजा देने के साथ-साथ पीड़ितों को राहत देना भी शामिल है। मुआवजा राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह राय की ओर से यह स्वीकारोक्ति भी है कि पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हालांकि, यह भी सच है कि किसी भी राशि से एक परिवार के दो सदस्यों की क्षति की भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती। साथियों बात अगर हम इस केस में मृतक बाप बेटे के परिवार की प्रतिक्रिया- दर्द, संतोष और अधूरी शांति को समझने की करें तो फैसले के बाद जयराज और बेनिक्स के परिवार ने मिश्रित भावनाएँ व्यक्त कीं। एक ओर उन्हें यह संतोष था कि छह वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिला, वहीं दूसरी ओर उनके मन में यह पीड़ा भी थी कि उनके प्रियजन कभी वापस नहीं आएंगे।परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए न्याय है जो पुलिस अत्याचार का शिकार होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से भविष्य में ऐसे मामलों में कमी आने की सटीक रूप से उम्मीद है। साथियों बात अगर हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया मानवाधिकारों की वैश्विक चिंता के परिपेक्ष में समझने की करें तो इस मामले ने न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे पुलिस सुधार की आवश्यकता का उदाहरण बताया।विश्व स्तर पर यह सवाल उठाया गया कि क्या कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इतनी शक्ति दी जानी चाहिए कि वे उसका दुरुपयोग कर सकें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/08862)

नामित सदस्यों ने ली शपथ

कसानगंज कुशीनगर। शासन द्वारा नामित सदस्य राधेश्याम पासवान मिथिलेश अग्रहरि व गुंजन मिश्रा को उप जिलाधिकारी विनोद गुप्ता ने बुधवार को कसानगंज नगर पंचायत के सभागार में शपथ दिलवाया इस मौके पर मुख्य अतिथि रामकोला विधायक विनय प्रकाश गोंड़ ने कहा कि शासन से नामित सदस्यों को नगर के विकास के लिए आगे आना होगा। उनको जनप्रतिनिधि के साथ-साथ अपने दायित्वों का अपने कार्यो का निर्वहन करना होगा वहीं उप जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा निम्न सदस्य नगर व शासन के कार्यो को देखते हुए कार्य करेंगे। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सोनू खेतान, आनंद मिश्रा,सभासद मो आरिफ, विजय कन्नौजिया, बैजनाथ, ढोरा राइन, शालू जायसवाल, रमेश मोदनवाल, विश्वजीत सिंह, मणिनदर अग्रहरि भोला साहनी दृगराज कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे।

कुशीनगर में निजी स्कूलों पर सख्ती- NCERT/SCERT किताबें अनिवार्य, मनमानी फीस व अवैध वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश

पडरौना, कुशीनगर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जनपद में संचालित सभी मान्यता प्राप्त अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेश में पाठ्यपुस्तकों, शुल्क वसूली और स्कूल वाहनों के संचालन को लेकर सख्ती बरतने को कहा गया है। आदेश के अनुसार अब सभी स्कूलों में NCERT एवं SCERT की पाठ्यपुस्तकों को ही अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। किसी भी निजी प्रकाशन की किताबें लागू पाए जाने पर संबंधित प्रबंधक व प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, शुल्क वसूली को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित मानक के अनुसार ही फीस ली जाए। छात्रों या अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

स्कूल वाहनों को लेकर भी प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाया है। UP Integrated School Vehicle Management Portal पर सभी स्कूल वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के वाहन संचालन पर रोक लगाई गई है। साथ ही निजी वाहनों के जरिए छात्रों के परिवहन को नियमों का उल्लंघन बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही के चलते कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी। इसके अलावा, बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। ऐसे विद्यालय संचालित करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना तथा उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये तक दंड का प्रावधान बताया गया है। जिला प्रशासन ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कार्रवाई रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराएं।

अंबेडकर जयंती को लेकर सपा की बैठक, 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाने की तैयारी

कसानगंज समाजवादी पार्टी की ओर से डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने को लेकर बुधवार को वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रत्याशी रमेश जायसवाल के आवास पर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता निठुरी राजभर ने की। बैठक में तय हुआ कि 14 अप्रैल को रामकोला विधानसभा क्षेत्र के 10 बूथों के 35 सेक्टरों पर जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। वक्ताओं ने अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को अपनाने पर जोर दिया। बैठक में कैलाश कनौजिया, हरीश कुमार राणा, मंटू राजभर, छोटेलाल यादव, संत जी, परवेज आलम, भोला यादव, आदि मौजूद रहे।

फायरिंग कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई - मुठभेड़ में एक घायल, दो आरोपी गिरफ्तार

(कुशीनगर)। सभासद के दरवाजे पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। कार्रवाई स्थानीय पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त पहल पर की गई। पुलिस के अनुसार, 6/7 अप्रैल की रात फायरिंग कांड में वांछित अभियुक्त आदित्य साहनी पुत्र कमलेश साहनी, निवासी ग्राम बभनौली, को हसनगंज क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया।

मौके से एक .32 बोर पिस्टल, खोखा, दो जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 1000 रुपये नकद बरामद किए गए। हालांकि, उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह,

थानाध्यक्ष दीपक सिंह, स्वाट प्रभारी स्वतंत्र सिंह, चौकी प्रभारी बबलू सोनकर और अंकित सिंह सहित कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। वहीं, इसी मामले में पुलिस ने बुधवार को हिस्ट्रीशीटर सूजा खान पुत्र मुस्ताक, निवासी वार्ड 11 मंगल बाजार,

स्वाट व स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर समेत मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार

कसानगंज को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ थाना कसानगंज में पहले से ही 8 संगीन मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस उसे काफी समय से तलाश रही थी। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि फायरिंग कांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में भरोसा बढ़ा है।

खड्डा में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल, पैर कुचला- चालक फरार, जांच शुरू

खड्डा (कुशीनगर)। तहसील क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक का बायां पैर ट्रैक्टर के नीचे कुचल गया, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना भुजौली बाजार के पास बेलवानिया चौराहे से पनिहावा मार्ग पर हुई। घायल की पहचान सुभाष निषाद निवासी कटाई भरपूरवा भक्तोली के रूप में हुई है। वह अपनी ससुराल छितौनी नगर पंचायत से बुधवार सुबह बाइक से घर लौट रहे थे। बताया जाता है कि बेलवानिया चौराहे की ओर बढ़ते समय सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े और ट्रैक्टर की चपेट में आ गए, जिससे उनका पैर बुरी तरह कुचल गया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर मौके पर छोड़कर फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्कहा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने फरार चालक की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अभ्युदय योजना से मिली उड़ान, कुशीनगर के विद्या भूषण सिंह बने नायब तहसीलदार

कुशीनगर। (वेबवार्ता) आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियों के बावजूद सफलता हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन जनपद के विद्या भूषण सिंह ने यह साबित कर दिखाया है कि सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलने पर प्रतिभा हर बाधा को पार कर सकती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सम्मिलित राय/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (UPPCS-2024) में सफलता प्राप्त कर नायब तहसीलदार पद हासिल किया है। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग एवं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को दिया है, जिसने उनकी तैयारी को नई दिशा दी। समाज कल्याण विभाग द्वारा लखनऊ के गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में निःशुल्क आवासीय कोचिंग संचालित की जा रही है, जहां अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर वातावरण मिलता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं, जिनके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की सशक्त तैयारी कराई जा रही है। इन केंद्रों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित कक्षाएं, उत्तर लेखन अभ्यास और मॉडल टेस्ट आयोजित कर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। संयुक्त निदेशक आनंद कुमार सिंह के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को कोचिंग अवधि के दौरान निःशुल्क हॉस्टल, भोजन और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 75 जनपदों में 166 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से संचालित है, जहां यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई, नीट, एनडीए और सीडीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। समाज कल्याण राय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली युवा आर्थिक अभाव के कारण अपने सपनों से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि अभ्युदय योजना और निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से युवाओं को समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और विद्या भूषण सिंह की सफलता इस बात का प्रमाण है कि उचित मार्गदर्शन मिलने पर प्रदेश के युवा किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट

फाजिलनगर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 5 मई को मतदान

कुशीनगर। नगर पंचायत फाजिलनगर के रिक्त अध्यक्ष पद (अनारक्षित) पर उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि राय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में यह चुनाव निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कराया जाएगा, बशर्ते यह किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 10 अप्रैल से 16 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 18 अप्रैल को होगी, जबकि अभ्यर्थन वापसी 20 अप्रैल को निर्धारित है। इसके बाद 21 अप्रैल को प्रतीक आवंटन किया जाएगा। मतदान 5 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगा, जबकि मतगणना 7 मई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी। निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए डिप्टी कलेक्टर सर्वेश सिंह को रिटर्निंग अधिकारी तथा तहसीलदार कसया धर्मवीर सिंह को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नामित किया गया है।

कमर्शियल गैस सप्लाई ठप, व्यापार मंडल ने उठाई आवाज

जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र सौंपा तत्काल कार्यवाही की मांग

भटनी देवरिया।

भटनी क्षेत्र में सुमित्रा इंडेन गैस सर्विस द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद किए जाने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उद्योग व्यापार मंडल भटनी ने इस गंभीर समस्या को लेकर जिलापूर्ति अधिकारी देवरिया को पत्र सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता एडवोकेट के दिए गए पत्र में बताया गया है कि सुमित्रा इंडेन गैस सर्विस द्वारा अपने ही

नियमित उपभोक्ताओं को कमर्शियल गैस सिलेंडर छोटा व बड़े की सप्लाई नहीं दी जा रही है। एजेंसी का कहना है कि प्लांट से ही कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद है, जिससे व्यापारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पत्र में कहा गया है कि शादी-विवाह और अन्य आयोजनों का सीजन चल रहा है।

होटल, मिठाई की दुकानें, ढाबा और छोटे-बड़े व्यापारी कमर्शियल गैस पर निर्भर हैं। सप्लाई बंद होने से दुकानों के संचालन में दिक्कत आ रही है और व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। उद्योग व्यापार मंडल भटनी ने जिलापूर्ति अधिकारी से मांग की है कि सुमित्रा इंडेन गैस सर्विस की कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई तत्काल प्रभाव से बहाल कराई जाए, ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके।

जब इस सम्बंध में वार्ता करने को मिलाया फ़ोन, लेकिन नहीं उठा मोबाइल

इस संबंध में इंडेन ऑयल के अधिकारियों तथा सुमित्रा इंडेन गैस सर्विस से वार्ता करने के लिए कई बार मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी का मोबाइल फोन नहीं उठा। इससे मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी और व्यापारियों में नाराजगी बनी हुई है।

देवरिया के विद्युत संकट का स्थायी समाधानः कतरारी में बनेगा पांचवा बिजली घर, लोड शेडिंग से मिलेगी बड़ी राहत

देवरिया।

शहर की लगातार बढ़ती आबादी और विद्युत उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने जनपद के पुराने बिजली ढांचे पर भारी दबाव पैदा कर दिया था। अब तक शहर की पूरी आपूर्ति केवल चार बिजली घरों के भरोसे टिकी थी, जिसके चलते ओवरलोडिंग और कटौती एक आम समस्या बन गई थी। लेकिन अब इस संकट का स्थायी समाधान निकलता दिख रहा है। शहर की बिजली व्यवस्था को सशक्त करने के लिए पांचवें नए बिजली घर की स्थापना को हरी झंडी मिल गई है, जिसका निर्माण कतरारी स्थित विद्युत उत्पादन केंद्र की भूमि पर किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना को धरातल पर उतारने के पीछे सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की सक्रियता और चार वर्षों का निरंतर प्रयास एक बड़ी वजह बनकर उभरा है। सदर विधायक के रिपोर्ट कार्ड के अनुसार, सबसे बड़ी चुनौती शहर के भीतर जमीन की उपलब्धता को लेकर थी। जिला प्रशासन द्वारा उपयुक्त भूमि न मिल पाने की स्थिति में वैकल्पिक रास्तों पर विचार किया गया और अंततः कतरारी में भूमि की व्यवस्था कराकर शासन से बजट की स्वीकृति हासिल की गई। नए बिजली घर के चालू

होने से शहर के चारों पुराने उपकेंद्रों पर लोड कम होगा और उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। पिछले चार वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनपद के विद्युत ढांचे में व्यापक बदलाव की कोशिशें दिखी हैं। बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए उसरा, नाथनगर, गौरी बाजार और भटवलिया जैसे प्रमुख केंद्रों पर 10 एमवीए के चार नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जबकि रामलीला मैदान स्थित बिजली घर की क्षमता को बढ़ाकर 25 एमवीए कर दिया गया है। बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए 440 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए और करीब 550 किलोमीटर लंबी नई बिजली लाइनें बिछाई गई हैं। साथ ही, जर्जर तारों और पोलों को बदलने के लिए 473 चिन्हित स्थानों पर युद्ध स्तर पर काम

4 साल में बदला बिजली का बुनियादी ढांचा- 440 नए ट्रांसफार्मर और 550 किलोमीटर तारों के जाल से रोशन होगा जनपद

अड़चनें खत्म- जिला प्रशासन और शासन के समन्वय से कतरारी में मिली जमीन, जल्द शुरू होगा नए सब-स्टेशन का निर्माण

किया गया है। तकनीकी सुधारों के क्रम में नौ नए फीडर भी शुरू किए गए हैं, जिनसे रामलीला मैदान, भटवलिया, नाथनगर और बैतालपुर जैसे क्षेत्रों में बिजली का वितरण पहले से अधिक संतुलित हुआ है। विशेष रूप से नगर पंचायत बैतालपुर के फीडर को अलग करना एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण और शहरी लोड का अंतर स्पष्ट हुआ है। यही प्रक्रिया अब गौरीबाजार में भी दोहराई जा रही है। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के अनुसार, इन प्रयासों का उद्देश्य देवरिया को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप एक आधुनिक और निर्बाध विद्युत प्रणाली प्रदान करना है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि कतरारी बिजली घर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जो शहर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

राजधानी में पलायन की पीड़ा से परेशान हैं प्रवासी, बोले- मकान मालिक नहीं जलाने दे रहे लकड़ी-कोयला

नई दिल्ली । एलपीजी संकट ने राजधानी में गरीब मजदूरों की जिंदगी को इस कदर झकझोर दिया है कि अब उनके सामने दिल्ली छोड़कर गांव लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। महंगी दामों पर गैस खरीदने के लिए जेब में पैसे है लेकिन अगर पैसे सिलिंडर पर खर्च कर दिए गांव में बच्चों और परिजनों के लिए क्या भेजेंगे। यही चिंता है जो मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। लकड़ी और कोयले पर अगर खाना बनाना चाहें तो मकान मालिक मना कर देते हैं। ऐसे में कई मजदूर उधार लेकर घर लौट रहे है। सोचा था कि कुछ पैसे अगर जुट गए तो गांव का खंडहर में तब्दील हो रहे घर की मरम्मत करवा लूंगा लेकिन गैस संकट ने बजट ऐसा बिगाड़ा कि अब गांव वापस जाना मजबूरी बन गया है। गैस बहुत महंगी है, लकड़ी जल्दी मिलती नहीं और मिल भी जाए तो 12 घंटे काम कर थक कर चूर हो जाता हूं। ऐसे में चूल्हा कौन फूंकेगा? ये कहना है जगदेपुर निवासी करम चंद का, जो गैस संकट के चलते पलायन के लिए मजबूर है। 600 रुपये दिहाड़ी में कहां तक बाहर से खा सकता हूं। बच्चे भी पालने हैं अब गैस संकट ने तो कमर ही तोड़ दी है। दोनों हाथों में अपनी गृहस्थी समेटे बिलासपुर अपने गांव जा रहे रोहेल ने अपना दुखड़ा रोते हुए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए जमकर कोसा। बिहार से कमाने आए अनिल ने बताया कि सिलिंडर इतना महंगा मिल रहा है कि उसे खरीदना हम जैसे मजदूरू के लिए संभव नहीं है। 13 हजार के वेतन में तेल, आटा खरीदूं या सिलिंडर, इस लिए गांव वापस जाना ही उचित समझ आया। गैस की कमी की शिकायतों के बीच दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति बढ़ा दी है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की, प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद वर्ग के लिए सिलिंडर की संख्या दोगुनी कर दी गई है। पांच किलो के छोटे सिलेंडर प्रतिदिन 1368 उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए कॉमर्शियल एलपीजी कोटा 180 से बढ़कर 360 सिलिंडर प्रतिदिन कर दिया गया है। कुल दैनिक आपूर्ति सीमा 6,480 सिलिंडर तय की गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। मंत्री के अनुसार, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए गए है कि वे तय सीमा का सख्ती से पालन करें और यदि किसी श्रेणी में अतिरिक्त स्टॉक बचता है, तो जरूरतमंद वर्गों में वितरित करें। वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है और एक केंद्रीकृत डेटाबेस के जरिए डुप्लीकेशन रोकने के उपाय किए गए है। सरकारी स्तर पर भले ही गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया जा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आनंद विहार, नई और पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर इन दिनों पलायन करने वाले लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिहार जा रहे प्रेम मौर्य ने बताया कि वे 10 दिन पहले बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली आए थे। दिन भर काम करने पर 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है। अब आप ही बताइए, अगर गैस सिलेंडर भी 400 रुपये किलो मिलेगा, तो हम खाएंगे क्या? दो-तीन दिन भूखा रहा, दोस्तों ने खिलाया।

कैबिनेट ने पांच बड़े फैसलों को दी मंजूरी

सरकार ने खोला खजाना- डीएपी खाद नहीं होगी महंगी, जयपुर में दौड़ेगी नई मेट्रो

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आम आदमी, किसानों और देश के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कई अहम मुहर लगी हैं.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने कुल 1 लाख 74 हजार 207 करोड़ रुपये के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स को अपनी मंजूरी दे दी है.

1- किसानों को खाद पर भारी सब्सिडी (41,534 करोड़ रुपये)

सरकार ने आगामी खरीफ फसलों के लिए डीएपी और एनकेपीएस जैसे जरूरी उर्वरकों पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है. इस मद में 41,534 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि दुनिया भर में कीमतें भले ही ऊपर-नीचे हों, लेकिन भारत में किसानों को डीएपी की बोरी पहले की तरह ही महज 1350 रुपये में मिलती रहेगी. लागत का अतिरिक्त बोझ सरकार खुद उठाएगी.

2- राजस्थान में HPCL रिफाइनरी का रास्ता साफ (79,459 करोड़ रुपये)

औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए, सरकार ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 79,459 करोड़ रुपये का बड़ा फंड

स्वीकृत किया है. यह प्रोजेक्ट न सिर्फ राजस्थान की आर्थिक तस्वीर बदलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा करेगा.

3- जयपुर मेट्रो के फेज-2 को हरी झंडी (13,038 करोड़ रुपये)

जयपुर शहर में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए, 41 किलोमीटर लंबे जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण (फेज-2) के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर 13,038 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसके बनने से लाखों दैनिक यात्रियों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगा.

4- कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (26,070 करोड़ रुपये)

भविष्य में बिजली की बढ़ती मांग को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सरकार ने 1,720 मेगावाट क्षमता वाले 'कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट' को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है. इस विशाल जलविद्युत परियोजना पर 26,070 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

5- कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (14,106 करोड़ रुपये)

देश की ऊर्जा सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत 1,200 मेगावाट के 'कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट' पर भी मुहर लगाई गई है, जिसके निर्माण पर 14,106 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

सीएम योगी का निर्देश- बेमौसम बारिश से नुकसान का 24 घंटे में किसानों को दिया जाए मुआवजा

लखनऊ । प्रदेश में बेमौसम बारिश आगजनी की घटनाओं से रबी की फसलों को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश दिए है। सीएम आवास पर बारिश और तूफान से फसल नुकसान पर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी मौके पर जाकर बारिश से हुए नुकसान का तुरंत आकलन कर किसानों को समय पर मुआवजा दिया जाए।

किसानों के साथ खड़ी है योगी सरकार

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लगातार किसानों के संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

खुद फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लें अधिकारी

सीएम योगी ने जिला अधिकारियों, विशेष रूप से डीएम को निर्देश दिया कि वे खुद फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लें और प्रभावित किसानों तक सीधे पहुंच बनाएं।

साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी मौके पर मौजूद रहकर राहत कार्यों को तेज करने को कहा गया है।

मुआवजे में न हो देरी

उन्होंने यह भी जोर दिया कि फसलों के नुकसान का सही और त्वरित सर्वे कराया जाए, ताकि मुआवजे में देरी न हो। शासन स्तर पर सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए है, जिससे राहत कार्य प्रभावी तरीके से पूरे हो सकें। सरकार का कहना है कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और उनकी आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 474 करोड़ के हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रगति की समीक्षा की

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रगति का आकलन करने के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 474 करोड़ की महत्वाकांक्षी पहल को विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से पीपीपी मॉडल पर लागू किया जा रहा है। बैठक में एमडी HARTRON श्री ने गणेशन के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि प्रोग्राम की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट जनवरी 2026 में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। यह मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग की स्वीकृति के पश्चात प्रदान की गई। कार्यक्रम की विस्तृत

एआई प्रोग्राम राय एक लाख से अधिक युवाओं को निपुण करेगा, सो से अधिक स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करेगा

परियोजना रिपोर्ट आगामी जून 2026 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि राय के युवाओं को यादा से यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के तहत एक लाख से अधिक

युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने तथा 100 से अधिक स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह पहल भारतीय एआई मिशन के स्किलिंग एवं वर्कफोर्स डेवलपमेंट, स्टार्टअप फाइनेंसिंग एवं इनक्यूबेशन, कंप्यूटर एवं डेटा सेट, उपयोग मामलों एवं एप्लिकेशन तथा एथिकल एआई गवर्नेंस सहित पांच प्रमुख स्तंभ पर आधारित है। बैठक में बताया गया कि विश्व बैंक मिशन टीम के 6 एवं 7 अप्रैल को पंचकूला में हुए दो दिवसीय दौरा किया । दौरे के दौरान विभिन्न विभागों से एआई के संभावित उपयोग मामलों की पहचान करने को कहा गया है। इसमें विभागों को अपने सुझाव प्रस्तुत करने हेतु 15 दिनों का समय दिया गया है, जिसके बाद प्राथमिकता वाले उपयोग मामलों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राय सरकार एआई इनोवेशन सैंडबॉक्स स्थापित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है, जो «निवेश से पूर्व परीक्षण» प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में एआई समाधान की पहचान, सत्यापन एवं पायलट परीक्षण दिया जाएगा। यह सैंडबॉक्स पूर्णतः विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में दो प्रमुख एआई केंद्र स्थापित करने की योजना है। पंचकूला में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के सहयोग से हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी, जो उच्च-क्षमता कंप्यूटिंग अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम में नासकोम के सहयोग से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो स्टार्टअप इनक्यूबेशन एवं उद्योग सहयोग को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा तथा युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित करेगा।

हम मतदाता सूची से नाम हटाने के विरोध में फिर से अदालत जाएंगे - ममता बनर्जी

बंगाल । बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का विरोध करने के लिए फिर से अदालत का रुख करेगी। राय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पूरा होने पर लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाने के बाद उन्होंने यह टिप्पणी की।

बनर्जी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की कवायद को लेकर अपनी मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाकर आप तृणमूल कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे। नामों को हटाने के विरोध में हम फिर से अदालत जाएंगे। बनर्जी ने फरवरी में उच्चतम न्यायालय में दलीलें दी थीं, जिसमें उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में कुल

7.66 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 90.83 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि मतदाताओं का नाम हटाने का अनुपात अब भी 11.85 प्रतिशत से अधिक है। हुगली जिले के आरामबाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने भाजपा पर मतदाता सूचियों में हेरफेर करने और मतदाताओं को लुभाने के लिए धन की पेशकश करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग फोन पर लोगों को धमका रहा है। उन्होंने दावा किया, निर्वाचन आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। वह लोगों को फोन करके धमका रहा है और डरा रहा है।

ईरान-अमेरिका युद्ध विराम-ओवैसी बोले- विदेश नीति तीन घंटे का मजाक नहीं, लेबनान में जंगबंदी कराए सरकार

हैदराबाद। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम पर बनी सहमति पर एआईएमएआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विदेश नीति व आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा कोई तीन घंटे का मजाक नहीं है। इसे हल्के में लेना सही नहीं है। उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए कहा कि वह एक विफल राष्ट्र है। उसने जो भूमिका निभाई, वह भूमिका हमें निभानी चाहिए थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा कोई तीन घंटे का मजाक नहीं है। अगर कोई इसे ऐसे ही हल्के में

ले रहा है, तो यह ठीक नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो एक विफल राष्ट्र है, वह जो भूमिका निभा रहा है, वह हमें निभानी चाहिए थी। ठीक है, युद्ध विराम हुआ। मासूम लोगों की मौतें कम होंगी। मगर अभी भी वक्त है। हम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार से कहेंगे कि आप लेबनान में जंगबंदी कराइए।

खुलकर बोलना चाहिए कि लेबनान में इसाइल जो कर रहा है, वह गलत है। उसने लेबनान के 20 फीसदी भूभाग पर कब्जा कर लिया है। अगर हम इस खामोश रहेंगे, हम अक्साई चिन और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को कैसे वापस लेंगे? इस पर विचार करने की जरूरत है।

खरगे ने खेद जताया- गुजरात के अपमान पर सियासी रार!

कांग्रेस अध्यक्ष बोले- मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केरल में दिए अपने एक चुनावी भाषण पर सफाई दी है। उन्होंने अपने बयान पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। खरगे ने साफ किया कि उनका इरादा गुजरात के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कभी नहीं था।

उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों के प्रति उनके मन में हमेशा सर्वोच्च सम्मान रहा है और आगे भी रहेगा। यह विवाद तब शुरू हुआ जब खरगे ने केरल के इडुक्की जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। वहां उन्होंने केरल के लोगों की शिक्षा और

समझदारी की तारीफ की थी। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे उन लोगों को मूर्ख बना सकते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जैसा कि गुजरात और कुछ अन्य जगहों पर होता है। उन्होंने कहा था कि केरल के जागरूक मतदाताओं को गुमराह करना मुमकिन नहीं है। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे कांग्रेस की बांटो और राज करो वाली मानसिकता बताया। वहीं, वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इस टिप्पणी को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या महात्मा गांधी, सरदार पटेल और मोरारजी देसाई जैसे महान व्यक्तित्व भी अनपढ़ थे भाजपा ने खरगे से सार्वजनिक माफी की मांग की थी और सोनिया गांधी व राहुल गांधी से भी इस पर रुख साफ करने को कहा था।

एमपी के बड़वानी में भूकंप के झटके, 3.4 तीव्रता से कांपी धरती

इंदौर। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में बुधवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। अचानक जमीन में कंपन महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 दर्ज की गई है। जिले के सेंधवा और आसपास के इलाकों में लोगों ने हल्का कंपन महसूस किया। विशेष रूप से सेंधवा और ग्राम मोहीपुरा में झटकों के बाद लोग सतर्क होकर घरों से बाहर आ गए।

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद - लेबनान पर इजराइली हमले में 254 मौत के बाद फैसला, ट्रम्प बोले- सीजफायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं

तेल अवीव ।

इजराइल ने बुधवार को लेबनान में कई जगहों पर एयरस्ट्राइक की। इन हमलों में 254 लोग मारे गए और 1,165 लोग घायल हो गए। लेबनान की नागरिक सुरक्षा टीम के अनुसार, मारे गए लोग लेबनान के बेरूत, बालबेक, हर्मेल, नबातीह, अले डिस्ट्रिक्ट, सिडोन और टायर के थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इजराइली हमले के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया है। इससे पहले उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी थी कि अगर सीजफायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया, तो यह समझौता टूट जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि ईरान के साथ सीजफायर प्लान में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का सीजफायर प्लान भेजा था, उसमें हिजबुल्लाह पर हमले रोकने की मांग की गई थी। तब इजराइल ने कहा था कि वो हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकेगा। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 40 दिन बाद 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बनी है। ट्रम्प ने बताया कि यह फैसला पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। सीजफायर से पहले ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वह उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी धमकी दी थी। न्यूयॉर्क

टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल से संभव हो पाई।

पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीजफायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे।

ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को औपचारिक बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी।

ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा

ट्रम्प ने बताया कि ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा है। उन्होंने कहा कि इस पर आगे बातचीत की जा सकती है। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया है कि अमेरिका ने उसका 10 पॉइंट प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। काउंसिल के मुताबिक यह समझौता ईरान की शर्तों पर हुआ है और इसे देश की जीत बताया है।

ओमान ने होर्मुज में टोल टैक्स वसूलने की ईरानी मांग का विरोध किया

ओमान ने ईरान की उस मांग का विरोध किया है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओमान ने कहा कि होर्मुज जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर किसी भी तरह का टोल नहीं लगाया जा सकता। यह एक इंटरनेशनल वाटरवे है, जहां से सभी देशों के जहाजों को बिना रुकावट और बिना शुल्क के गुजरने का अधिकार है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत ऐसे स्ट्रेट में फ्री ट्रांजिट का नियम लागू होता है। यानी कोई भी देश वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल नहीं ले सकता। आमतौर पर टोल सिर्फ कृत्रिम नहरों (जैसे स्वेज नहर) में लिया जाता है, प्राकृतिक समुद्री रास्तों में नहीं।

इजराइल ने बेरूत में लोगों को घर खाली करने की धमकी दी

ईरान जंग में सीजफायर के बाद भी इजराइल और हिजबुल्लाह में तनाव कम नहीं हुआ है। इजराइली सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से अपने घर खाली करने की चेतावनी दी है। ये इलाके घनी आबादी वाले है और यहां पहले से ही बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं। 2 मार्च के बाद से दोनों पक्षों के बीच हमले तेज हुए है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं।

शिपिंग कंपनियां होर्मुज से आवाजाही को लेकर अभी भी सतर्क

दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी मर्स्क ने कहा है कि सीजफायर से कुछ राहत जरूर मिल सकती है, खासकर होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को लेकर। हालांकि कंपनी ने साफ किया कि अभी हालात पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और वह किसी भी बड़े बदलाव से पहले स्थिति पर नजर बनाए रखेगी।